कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक 1602 /टीसी/2023 ग्वालियर, दिनांक 14.03.2023

प्रति

समस्त क्षेत्रीय/ अतिरिक्त क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी,

मध्यप्रदेश ।

विषय- Call before You Dig (CBuD) App के संबंध में ।

सन्दर्भ- 1. भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 03-01-2023

2. मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौघोगिकी विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 10/000//2021/41–2 दिनांक 13/03/2023

उपरोक्त विषय में लेख है कि दूर संचार मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार खुदाई से सम्बंधित समस्त एजेंसियो को भारत सरकार के CBuD App में रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है, अतः आपके कार्यालय में पंजीकृत समस्त Loader, Excavator, Rig Machine एवं खुदाई/ खनन कार्य के निमित्त निर्मित या अनुकूलित वाहन के स्वामियों को CBuD App में रजिस्ट्रेशन करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करे, ऐसे वाहन स्वामी, गूगल प्ले स्टोर से CBuD App डाउनलोड कर, यूजर टाइप में "Excavator" सेलेक्ट कर रजिस्ट्रेशन कर सकते है । किसी भी स्थान पर खुदाई/ खनन का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ऐसे वाहन स्वामी को CBuD App पर सूचना दर्ज कर खुदाई/ खनन की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

14/3

परिवहन आयुक्त

मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 1602/टीसी/ 2023 ग्वालियर दिनांक 14.03.2023

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौघोगिकी विभाग की ओर सूचनार्थ
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागीय उप परिवहन आयुक्तए मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

14/3

परिवहन आयुक्त

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय

क्रमांक SNT/10/0008/2021/41-2 भोपाल, दिनांक 13 मार्च, 2023

प्रति,

आयुक्त
परिवहन
मोती महल,ग्वालियर
मध्य प्रदेश

विषय: भारत सरकार, दूरसंचार विभाग के Call Before You Dig (CBuD) एप्प के संबंध में।

----00--

भारत सरकार के Call Before You Dig (CBuD) एप्प एप्लीकेशन को भारत सरकार, के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस एप्प का उपयोग उत्खननकर्ता (एक्सकेवेटर्स) और उपयोगिता संपत्ति मालिकों (यूटिलिटी एसेट्स ओनर्स) के बीच सुचारू समन्वय की सुविधा प्रदान करने के लिए यह एप्प विकसित किया गया है।

यह एप्प खुदाई करने वाली एजेंसियों को मौजूदा भूमिगत उपयोगिता संपत्तियों की उपलब्धता के बारे में जानकारी और प्रस्तावित आगामी उत्खनन गतिविधियों के बारे में उपयोगिता संपत्ति मालिकों को सूचित करने के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

इस एप्प के प्रभावी उपयोग के लिए खुदाई ठेकेदार स्वयं को एक्सकेवेटर के रूप में CBuD एप्लिकेशन पर पंजीकृत करेंगें एवं खुदाई की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात एप्प पर जानकारी अपलोड करेंगें।

परिवहन विभाग BackhoeLoader/Excavator Machines (खुदाई मशीनों) का पंजीकरण करता है। अत: अनुरोध है कि,खुदाई मशीनों के पंजीयनकर्ताओं को सूचित करने का कष्ट करें कि,CBuD एप्लिकेशन पर पंजीयन करना आवश्यक है, जिससे कि Telecom Infrastructure को बचाने/संरक्षित करने में सहयोग मिलेगा।

उक्त संबंध में विभाग को अवगत कराया जाना प्रस्तावित है।

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक SNT/10/0008/2021/41-2 भोपाल, दिनांक 13 मार्च, 2023

प्रतिलिपि :

प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

784

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012023-241640
CG-DL-E-03012023-241640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 2023/पौष 13, 1944
No. 05] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2023/ PAUSHA 13, 1944

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 06(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "सामान्य पोर्टल" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित और अधिसूचित पोर्टल या मोबाइल फ़ोन उपयोजन अभिप्रेत है;

(ग) "अनुज्ञप्तिधारी" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "सूचना" से सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की गई खुदाई या उत्खनन संबंधी पूर्व सूचना अभिप्रेत है;

(ड.) "तार अवसंरचना" में तार या तार लाइन और पोस्ट शामिल हैं;

(2) उन शब्दों और पदों के जो प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. **किसी संपत्ति की खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया** – (1) कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति के अधिकार के विधिक अधिकार से खुदाई या उत्खनन की इच्छा इस प्रकार से रखता हो जिससे कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से स्थापित की गई तार अवसंरचना या टेलीग्राफिक संचार को रुकावट डालने या बाधित करने की संभावना हो, तो वह व्यक्ति ऐसे अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व इस प्रकार की खुदाई या उत्खनन की सूचना, सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करके अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सूचना में विधिक अधिकार का उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम और पता, एजेंसी का ब्यौरा, पता, खुदाई शुरू करने की तारीख और समय, खुदाई का विवरण और स्थान तथा इस प्रकार की खुदाई या उत्खनन करने के कारण शामिल किए जाएंगे।

(3) अनुज्ञप्तिधारी उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्रस्तुत करने पर संपत्ति से संबंद्ध किसी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वामित्व वाली या नियंत्रित या तार अवसंरचना का ब्यौरा सामान्य पोर्टल के माध्यम से यथा शीघ्र उपलब्ध कराएगा जिसका प्रयोग वह तार अवसंरचना को क्षति पहुँचाए बिना समन्वय के लिए पूर्वाविधानी उपायों के साथ-साथ अधिकार के विधिक प्रयोग के लिए करना चाहता है।

(4) खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, उप-नियम (3) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए पूर्वाविधानी उपायों पर उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

(5) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 19(क) के अनुसार विहित समय के भीतर ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराता है तो खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति इसके पश्चात संपत्ति की खुदाई या उत्खनन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. **नियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए नुकसानी प्रभार** – (1) कोई व्यक्ति, जिसने किसी संपत्ति की खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार का प्रयोग इस ढंग से किया हो, जिससे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिवत रखे गए तार अवसंरचना के बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है, वह तार प्राधिकारी को नुकसानी प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नुकसानी प्रभार की गणना ऐसे खर्चों के आधार पर की जाएगी जैसा नुकसानी के प्रत्यावर्तन में उपगत किया जाए।

[फा. सं. 2-16/2022- नीति]

आनंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2023

G.S.R. 06(E).— In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Telegraph (Infrastructure Safety) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** -(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(b) "common portal" means a portal or mobile phone application developed and notified by the Central Government for the purposes of these rules;

(c) "licensee" means any person holding a license under sub-section (1) of section 4 of the act.

(d) "notice" means prior information of digging or excavation submitted through common portal.

(e) "telegraph infrastructure" includes a telegraph or a telegraph line and post;

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. **Procedure for exercising of legal right to dig or excavate any property.** — (1) Any person desiring to dig or excavate in the legal exercise of a right with any property in such a manner as is likely to cause damage to a telegraph infrastructure or to interrupt or interfere with telegraphic communication which has been duly placed in accordance with the provisions of the Act, shall give notice to licensee through common portal, by submitting the information of such digging or excavation, prior to the commencement of such exercise.

(2) The notice under sub-rule (1) shall include the name and address of the person exercising the legal right, agency details, contact details, date and time of start of the exercise, description and location of the exercise, and the reasons for such digging or excavation.

(3) The licensee shall, on submission of notice by the person under sub-rule (1), as expeditiously as possible provide through the common portal, the details of telegraph infrastructure owned or control or managed by such licensee, falling under or over or along the property with which the person intends to deal in legal exercise of the right, along with precautionary measures for coordination in avoiding damages to the telegraph infrastructure.

(4) The person exercising legal right to dig or excavate shall take appropriate action on precautionary measures provided by the licensee as per sub-rule (3).

(5) In case no licensee provides details within the prescribed time as per section 19(A) of the Act, the person having legal right to dig or excavate shall be free to dig or excavate the property thereafter.

4. **Damage charges for breach of provisions of the rule.** — (1) Any person, who in exercise of legal right has dug or has excavated any property in such a manner causing damage to a telegraph infrastructure duly placed in accordance with the provisions of the Act shall be liable to pay the damage charges to the telegraph authority:

(2) The damage charges under sub-rule (1) shall be computed based on such expenses as may be incurred in restoring damages.

[F. No. 2-16/2022-Policy]

ANAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

487

के. राजारामन, भा. प्र. से.
सचिव
K. Rajaraman, IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications

D.O. 3-1/2022-NBM
Dated 7th February, 2023

Dear Chief Secretary,

I appreciate your efforts in onboarding key infrastructure departments onto **"Call Before u Dig" (CBuD) Mobile app** based on my letter dated 02-12-2022. The CBuD Mobile App is likely to be launched at National level by Hon'ble Prime Minister in mid-March. The State Government departments and agencies need to onboard contact details of all concerned officials of infrastructure utility asset owner agencies of the State/UTs in CBuD App to receive notifications of the enquiries made by other agencies/contractors/members of public likely to undertake excavation activities in public places enabling them to safeguard the assets from damages during excavation. **All agencies intending to carry out excavations (Government or private) need to be mandated by the States/UTs by notification to carry out any type of excavation / digging only after prior intimation through CBuD App.**

2. DoT has issued **"Indian Telegraph (Infrastructure Safety) Rules, 2022"** (ITIS Rules, 2022) on 03rd January, 2023, which mandates to use Portal or Mobile App and casting liability on excavator / excavation agencies to notify any likely excavation through the app to the telegraph / telecom licensee owning or managing telegraph infrastructure. Any damage caused due to negligence and liable to pay damage charges. (Copy of rules enclosed). CBuD App is supported by these provisions.

3. It may be noted that CBuD App is utility agnostic and supports any utility asset owner, viz., Water pipeline, Sewerage, Gas / Petroleum pipeline, Electric Cables etc. owned / managed by various State Departments/ Agencies. To support technical features of CBuD App for other utilities, State/UTs may also come out with similar rules mandating excavators to inform State utility agencies also through CBuD App prior to commencement of excavation activity.

4. In view of above, it is requested that States/UTs may adopt ITIS Rules, 2022 and notify similar rules or make amendments to the existing rules. State/UT are also requested to direct all State Departments to configure contact details of their concerned officers in CBuD App and mandate all excavating agencies to onboard themselves on the CBuD App before 28th February 2023. A list of Departments/Agencies who may be onboarded on CBuD app is attached.

With regards.

Yours Sincerely

(K. Rajaraman)

Chief Secretaries of all States/UTs

488

GoI Letter From Secretary

Annexure

List of Agencies who may onboard themselves on CBuD App

A. Utility Asset Owning Agencies/Departments who can be onboarded on CBuD App

Sr No	Probable Department /Agency as Asset Owner	Agency CBuD Nodal	Agency CBuD District User
1	Water Supply Agency	State or Regional agency division officer	Executive Engineer or official
2	Water Resource Agencies	State or Regional agency division officer	Executive Engineer or official
3	Sewerage maintenance agencies	Regional office Nodal	municipal corporation official
4	Underground Electric Cable Agencies e.g. DISCOM, Transmission Companies	State or Regional agency division officer	DISCOM District Incharge or official
5	State Gas Agencies	State or Regional incharge	City Gas pipeline incharge or official & area in-charges
6	State Petroleum agencies	State or Regional incharge	District level operation & maintenance officers
7	State Fibre Agencies	State Fibre Agency Nodal	State NOC manager and O&M District Incharge
8	Road agencies viz PWD, State Highways	State Nodal Incharge	Area incharge
9	Departments / agencies owning underground duct	Duct owning Authority	concerned district incharge of duct
10	Municipal Corporation/urban development	State/Regional officer	Executive Engineer
11	Panchayati Raj/rural development	State level rural development officer	BDO/BPRO or official
12	Metro rail	Metro development officer	Site incharge

B. Excavating Agencies and officer concerned that can be registered as in CBuD App

SrNo	Possible Agencies as Excavators	Officer concerned or Excavation Contractor
1	Road construction department / agencies e.g. PWD, State Highway agencies	Site engineer incharge OR Road construction contractor
2	Water pipeline laying departments and agencies	Project Engineer OR Contractor or its official
3	Sewerage line laying department / agencies	Project Engineer OR Contractor/its official
4	Underground electric cable laying department / agencies	Sub divisional engineer OR contractor's official
5	Gas Agencies	City incharge OR Excavation contractor or official
6	Petroleum agencies	Area incharge OR Excavation contractor or official
7	State/National Fibre Agencies	OFC Project incharge OR Contractor or official
8	Departments / agencies owning underground duct	Duct construction Incharge OR Contractor or its official
9	Municipal Corporation/urban development	Civil construction Contractor or official
10	Panchayati Raj/rural development	BDO/BPRO OR Excavation Contractor or Official
11	Metro rail	Site incharge OR Contractor or official
12	District development authority	Project Engineer OR Excavation Contractor or Official
13	Telecom service provider	TSP OFC laying incharge OR Contractor
14	Agencies owning Excavation Machinery registered with Transport departments	JCB / Excavator owner OR excavation agency official

त सरकार
र मंत्रालय, दूरसंचार विभाग
ार्यालय,वरिष्ठ उपमहा निदेशक
संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग
मध्य प्रदेश एल एस ए भोपाल - 462015

Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunication
Office of the Senior Deputy Director
Madhya Pradesh, Bhopal - 462015

SA
789

No. 42-2/2022-Sr.DDG-MPLSA (CBuD)

Dated at Bhopal 10-02-2023

To,
Principal Secretary (S & T)
Govt of Madhya Pradesh
Vallabh Bhawan 3, F-Wing
Bhopal, Madhya Pradesh

Sub: Soft launch of Call Before You Dig (CBuD) App. in Madhya Pradesh.

As you may aware, the Call Before You Dig (CBuD) app, developed by BISAG-N, has beenlaunched in the state of Gujarat and UT of Dadra and Nagar Haveli. It has now been decided by Department of Telecommunication to open the CBuD app across all states/UTsincluding MP for accepting digging enquiry and soft launch the app so as to gather more feedback.

It is now requested that following activities be undertaken on priority as CBuD app is going to be inaugurated by Hon'ble PM in the first week of March 2023:

1. To arrange CBuD Training and Awareness program/Workshop - DOT MP LSA has already organised a CBuD Training and Awareness program/Workshop for State Nodal, State Departments/Utility agencies on dated 27th January 2023 at Bhopal. Similar awareness programme may be arranged by State Nodal to further disseminate the CBUD application.

2. To expedite creation of Asset owner at all levels from Departments level to District level. It is mentioned that so far 09 Departmental nodal officers of MP State have been created. Asset owner creation for Department level, Utility agency level and District level is still pending for most of the departments in MP state

3. To instruct all state departments that while granting the digging approval, the departments should mention clearly in their approval letter, the use of CBuD App before commencing any type of digging anywhere in the State.

4. All Excavation / digging agencies to be mandated by State Govt. to do any type of excavation only after prior intimation through CBuD App.

5. To raise the Excavation/Digging Enquiry in CBuD App as it is now opened across all States/UTs for accepting Excavation/Digging enquiry.

10.02.23

(Radheshyam Parmar)
Dy Director General (Rural2)
MPLSA, Bhopal